



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## (असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यसभा सभा द्वारा प्रकाशित

चिन्ह, शनिवार, 18 अगस्त, 1984/27 भावण, 1986

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला-२, 18 अगस्त, 1984

क्रमांक एल० एल० आर०-डी०(६) १२/८४—हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विनिर्दिष्ट परीक्षाओं में अनाचार का निवारण विधेयक, 1984(1984 का विधेयक संख्यांक १५) जैसा कि राष्ट्रपति द्वारा “भारत के संविधान के अनुच्छेद 201” के अन्तर्गत दिनांक 30-7-1984 को अनुमति किया गया, को संविधान के अनुच्छेद

348 (3) के अन्तर्गत अपेक्षित इसके प्राधिकृत अंग्रेजी पाठ सहित सर्वसाधारण की जानकारी के लिये राजपत्र हिमाचल प्रदेश में 1984 का अधिनियम संख्यांक 19 के रूप में प्रकाशित किया जाता है।

वेद प्रकाश भट्टनागर,  
• सचिव (विधि)

1984 का अधिनियम संख्यांक 19.

हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड या अन्य विनिर्दिष्ट परीक्षाओं  
में अनाचार का निवारण अधिनियम, 1984

हिमाचल प्रदेश राज्य में किसी विश्वविद्यालय, बोर्ड या किसी अन्य विनिर्दिष्ट प्राविकरण की परीक्षाओं में अनाचार के निवारण का उपबन्ध करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैतीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश, विश्वविद्यालय, बोर्ड वा अन्य विनिर्दिष्ट परीक्षाओं में अनाचार का निवारण अधिनियम, 1984 है। संक्षिप्त नाम,  
विस्तार और  
प्रारम्भ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. इस अधिनियम में, जब तक नि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, परिभाषाएं

(क) “बोर्ड” से हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 1968 के अधीन हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए स्थापित स्कूल शिक्षा बोर्ड अभिप्रेत है;

(ख) “परीक्षा” से किसी विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा ली गई या लिए जाने के लिए प्रस्तावित कोई परीक्षा अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत ऐसे अन्य अधिनियमीय द्वारा ली गई या लिये जाने के लिए प्रस्तावित ऐसी अन्य परीक्षा भी है जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस निमित विनिर्दिष्ट किया या की जाए; और

(ग) “विश्वविद्यालय” से हिमाचल प्रदेश राज्य ने विधि द्वारा स्थापित कोई विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

3. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी परीक्षा में प्रश्न-पत्र बनाने के लिए नियुक्त किया जाता है, इस निमित उसको नियुक्त करने वाले प्राविकारी द्वारा उसे दिए गये लिखित अनुदेशों के अनुसार के सिवाए, किसी व्यक्ति को अपने द्वारा बनाए गए प्रश्न-पत्र या उसकी प्रति का प्रदाय नहीं करेगा या नहीं करायेगा या ऐसे प्रश्न-पत्र की अन्तर्वर्तसु की सूचना नहीं देगा या किसी भी रीति से उसका प्रचार नहीं करेगा। प्रश्न-पत्र बनाने वालों के कर्तव्य और उल्लंघन के लिए दण्ड।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा दोष-सिद्धि पर, कारावास से जिसकी श्रवण तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य जिन्हें प्रश्न-पत्रों का मुद्रण आदि सौंपा गया है और उल्लंघन के लिए दण्ड ।

ऐसे व्यक्तियों के कर्तव्य जिन्हें प्रश्न-पत्रों की अभिरक्षा सौंपी गई है और उल्लंघन के लिए दण्ड ।

परीक्षा होने से पूर्व किसी प्रश्न-पत्र के प्रदाय या प्रकाशन का प्रतिषेध ।

परीक्षा में नकल करने और प्रतिश्लेषण का प्रतिषेध ।

ग्रधीक्षक या वीक्षक पर हमला आदि ।

4. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी परीक्षा के प्रयोजनार्थ बनाए गए किसी प्रश्न-पत्र के नुद्रण, चक्केखन, टक्कंग या अन्यथा प्रतियां बनाने का कार्य सौंपा गया है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे वह कार्य सौंपा है, दिए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार किसी व्यक्ति को उसकी प्रति का प्रदाय नहीं करेगा या नहीं कराएगा या उसकी अन्तर्वस्तु की सूचना नहीं देगा या किसी भी रीत से उसका प्रचार नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, दोष-सिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

5. (1) कोई भी व्यक्ति, जिसे किसी परीक्षा के प्रयोजनार्थ बनाए गए किसी प्रश्न-पत्र की अभिरक्षा सौंपी गई है या वह अन्यथा उसके कब्जे में है, ऐसे प्राधिकारी द्वारा जिसने उसे उसकी अभिरक्षा सौंपी है या कब्जा दिया है उसे दिए गए लिखित अनुदेश के अनुसार के सिवाय, किसी भी व्यक्ति को उसकी प्रति का प्रदाय या दितरण नहीं करेगा या नहीं करायेगा या उसकी अन्तर्वस्तु की सूचना नहीं देगा या किसी भी रीत से उसका प्रचार नहीं करेगा ।

(2) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (1) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, दोष-सिद्धि पर, कारावास से जिस की अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

6. जो कोई विश्वविद्यालय, बोर्ड या परीक्षा से सम्बन्धित किसी अन्य प्राधिकरण के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार के सिवाय, अपने कब्जे में, किसी परीक्षा के लिए बनाया गया या बनाया गया तात्पर्यित कोई प्रश्न-पत्र रखेगा और परीक्षा होने से पूर्व वहाँ किसी प्रतिफल के लिए या अन्यथा, किसी व्यक्ति को, उसकी प्रति का प्रदाय करेगा या कराएगा या प्रदाय के लिए प्रस्थ पना करेगा या उसकी विषय-वस्तु की सूचना देगा या सूचना देने की प्रस्थानना करेगा, या किसी भी रीत में उसका प्रचार करेगा, वह, दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

7. जो कोई वीक्षक या परीक्षा के संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, परीक्षा भवन में या इसकी पांच सौ मीटर की परिधि के भीतर, परीक्षा के लिए बनाए गए प्रश्न-पत्र के उत्तरों को किसी पुस्तक, टिप्पणी या अन्य परीक्षार्थी की उत्तर-पुस्तिका से नकल करते हुए या परीक्षा में किसी अन्य के स्थान पर परीक्षा देते हुए या किसी अन्य अनुचित साधन का उपयोग करते हुए पाया जाएगा, वह दोषसिद्धि पर, कारावास से जिसकी अवधि तीन मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा ।

8. (1) परीक्षा-केन्द्र का प्रत्येक अधीक्षक और प्रत्येक वीक्षक परीक्षा या परीक्षाओं के दौरान और ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के प्रारम्भ होने से एक मास पूर्व और ठीक छः मास पश्चात तक की अवधि के लिए भारतीय दण्ड संहिता की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवक संग्रह जाएगा ।

1860 का 45 (2) उप-धारा (1) में उल्लिखित अधिकार के दौरान किसी परीक्षा-केन्द्र के अधीक्षक या वीक्षक पर हमला या आपराधिक बल प्रयोग, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 186 के अधीन दण्डनीय लोक सेवक के सार्वजनिक कृत्यों के निवेदन में स्वेच्छा से पहुंचाई गई बाधा समझी जाएगी ।

9. जो कोई; जिसे परीक्षा के संचालन, पर्यवेक्षण, उत्तर-पुस्तिकाओं के मूल्यांकन, परीक्षा परिणाम को सारणीबद्ध या प्रकाशित करने या परीक्षा से सम्बन्धित कोई अन्य कार्य या उसके परिणामों के प्रकाशन का कार्य मौपा गया है, उसे सौंपे गए निसी कृत्य को करने से इनकार करेगा, वह, दोषसिद्धि पर कारावास से जिसकी अधिकारी तीन मास तक की हो सकेगी, किन्तु जो एक मास से कम नहीं होगी या जुर्माने से जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, किन्तु जो दो हजार रुपये से कम का नहीं होगा, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा :

परन्तु न्यायालय अभिलिखित विशेष कारणों से एक मास से कम अधिकार के कारावास का या दो हजार रुपये से कम जुर्माने का, दण्डदेश भी अधिरोपित कर सकेगा ।

10. जो कोई इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, वह ऐसे अपराध के लिए उपबन्धित दण्ड से दण्डित किया जाएगा ।

1974 का 2

11. दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अन्तविष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञे और अज्ञानतीय होंगे :

अपराधों के दुष्प्रेरण के लिए दण्ड ।

अपराधों का संज्ञे और अज्ञानतीय होना ।

“परन्तु कोई व्यक्ति, जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो, गिरफ्तार किए जाने पर जमानत पर रिहा कर दिया जायेगा ।

1974 का 2

12. इस अधिनियम के अधीन सभी अपराधों का किसी भी प्रथम श्रेणी के न्यायिक मैजिस्ट्रेट द्वारा संक्षिप्त विचारण किया जाएगा और जहां तक हो सके ऐसे विचारण के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 262 से 265 तक के (जिसमें ये दोनों धाराएं सम्मिलित हैं) उपबन्ध लागू होंगे ।

अपराधों का संक्षिप्त विचारण ।

[Authoritative English text of the Himachal Pradesh, Vishav-Vidyalaya, Board ya Anya Vinirdisht Prikshaon mein Anachar ka Nivaran Adhinyam 1984 (1984 ka Adhinyam Sankhyank (19) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India].

Act No. 19 of 1984.

THE HIMACHAL PRADESH PREVENTION OF MALPRACTICES  
AT UNIVERSITY, BOARD OR OTHER SPECIFIED EXAMI-  
NATIONS ACT, 1984

AN  
ACT

to provide for preventing malpractices at Examinations of any University or the Board or any other specified authority in the State of Himachal Pradesh.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-fifth Year of the Republic of India, as follows:—

Short title,  
extent and  
commencement.

- (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Prevention of Malpractices at University, Board or other Specified Examinations Act, 1984.
- (2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.
- (3) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) “Board” means the Board of School Education for the State of Himachal Pradesh established under the Himachal Pradesh Board of School Education Act, 1968;
- (b) “Examination” means any examination held or proposed to be held by any University or the Board and includes such other examination held or proposed to be held by such other authority as may be specified in this behalf, from time to time, by the State Government by notification in the Official Gazette; and
- (c) “University” means any University established by law in the State of Himachal Pradesh.

14 of 1968

Duties of  
paper se-  
tters and  
punishment  
for contra-  
vention.

S  
P

3. (1) Any person who is appointed as a paper setter at any examination shall not supply or cause to be supplied the question paper drawn by him or a copy thereof or communicate the contents of such paper to any person or give publicity thereto in any manner, except in accordance with the instructions given to him in writing by his appointing authority in this behalf.
- (2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

4. (1) Any person who is entrusted with the work of printing, cyclostyling, typing or otherwise producing copies of any question paper set for the purposes of any examination shall not supply, or cause to be supplied, a copy thereof or communicate the contents thereof to any person or give publicity thereto in any manner, except in accordance with the instructions given to him in writing by the authority which entrusted the work to him.

Duties of persons entrusted with printing etc. of question papers and punishment for contravention.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

5. (1) Any person who is entrusted with the custody, or is otherwise in possession, of any question paper set for the purposes of any examination shall not supply or distribute or cause to be supplied or distributed any copy thereof or communicate the contents thereof to any person or give publicity thereto in any manner, except in accordance with the instructions given to him in writing by the authority which entrusted the custody or gave possession thereof to him.

Duties of persons entrusted with custody of question papers and punishment for contravention.

(2) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

6. Whoever has in his possession any question paper set or purported to be set for any examination and supplies or causes to be supplied or offers to supply a copy thereof, or communicates or offers to communicate the contents thereof, to any person, whether for any consideration or otherwise, or gives publicity thereto in any manner, except in accordance with the instructions issued in writing by an authorised officer of the University, Board or other authority concerned with the examination, at any time before the examination is held, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to one thousand rupees, or with both.

Prohibition of supply or publication of any question paper before examination is held.

7. Whoever is found in or within the periphery of 500 metres of an examination hall by the Invigilator or any other person appointed to supervise the conduct of the examination, copying answers to the question paper set at a examination, from any book, notes or answer paper of other candidate, or appearing at the examination for any other candidate or using any other unfair means, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months, or with fine which may extend to five hundred rupees, or with both.

Prohibition of copying and impersonating at examinations.

8. (1) Every Superintendent and every Invigilator of an examination centre shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code during the course of an examination or examinations and for a period of one month prior to the commencement of and of six months immediately following such examination or examinations.

Assault etc. on Superintendent or Invigilator.

(2) An assault on, or use of criminal force to, a Superintendent or an Invigilator of an examination centre during the period mentioned in sub-section (1) shall be deemed to be an obstruction voluntarily caused to a public servant in the discharge of his public functions punishable under section 186 of the Indian Penal Code.

Punishment for refusal to work for the conduct and declaration of results of an examination.

9. Whoever, being entrusted with the conduct, supervision, evaluation of answer sheets, tabulation or publication of results of an examination, or any other work connected with the examination or the publication of its result, refuses to discharge any function assigned to him, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months but shall not be less than one month, or with fine which may extend to five thousand rupees but shall not be less than two thousand rupees, or with both:

Provided that the court may, for any special reason to be recorded in writing, impose a sentence of imprisonment of less than one month or a fine of less than two thousand rupees.

Punishment for abetment of offences.

10. Whoever abets any offence punishable under this Act shall be punishable with the punishment provided for such an offence.

Offences to be cognizable and non-bailable.

11. Notwithstanding anything contained in Code of Criminal Procedure, 1973, all offences under this Act shall be cognizable offences and shall be non-bailable:

Provided that any person who has not attained the age of 18 years, when arrested shall be released on bail.

Short title, extent and commencement.

Definitions.

Offences to be tried summarily.

12. All offences under this Act shall be tried in a summary way by any Judicial Magistrate of the First Class and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 shall, as far as may be, apply to such trials.

Duties of paper setters and punishment for contravention.